जन पहल

अपनी बात

मित्रों ग्राम्या संस्थान ने वर्ष 2011 में डी0एफ0आई0डी0 एवं भारत सरकार के संयुक्त पहल पर पैक्स परियोजना की शुरुआत वाराणसी जनपद के दो प्रखण्डों सेवापुरी व बड़ागाँव के कुल 70 पंचायतों जिनमें कुल 122 गाँव में वंचित जन समुदायों के आजिविका की मूल सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयत्न कर रही है। इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती यह हैं कि लक्षित समुदायों में कैसे नेतृत्व को उभारा जाय और क्षमताएं बढ़ाई जाय जिससे परियोजना के बाद भी निरन्तरता बनी रहेगी। पैक्स की इन्ही कार्यक्रमों की कड़ी में यह नियोजित किया गया है कि परियोजना क्षेत्र की परिस्थितियों और बदलावों को लक्षित समुदायों की भागीदारी से निगरानी की जाय और उन्हे एक समाचार पत्र (न्यूज लेटर) के माध्यम से व्यापक फलक पर लाया जाय। तो इन्ही सपनों के साथ **जन पहल** के नाम से शुरु किया है। इसका चौथा अंक आपके हाथ में है। हमें लगता है कि सूचनाओं का विस्तार वंचित जनों के अधिकार सुनिश्चियन में मददगार होगा। जन पहल के अगले अंक में हमें आपके सुझावों का इन्तजार रहेगा।

ग्राम्या संस्थान की पहल-

जैसा कि आप लोगों ने पिछले अंक में पढ़ा कि गाम्या संस्थान पैक्स परियोजना के अर्न्तगत सेवापुरी व बड़ागाँव ब्लाक के गाँवों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकरी और जन पहल के माध्यम से औरो को भी बताने का कार्य कर रही है।इसी कड़ी में ग्राम्या संस्थान द्वारा महिला मंच की 76 महिलाओं को सामाजिक वहिष्करण पर सशक्तिकरण हेतु दो दिवसीय कार्याशाला का आयोजन रामडीह में किया गया। इस कार्यशाला में महिलाओं को निम्न मुद्दों पर समझ विकसीत की गई–

- मनरेगा।
- स्मार्ट कार्ड।
- जननी सुरक्षा योजना।
- नई विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन।
- राशन कार्ड।
- महिला मंच का ढाँचा।

इसी कड़ी में ग्राम्या संस्थान की टीम नई विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन में समुदाय की भागीदारी हो इसके लिए गाँव–गाँव में दीवाल लेखन, बैठक व संपर्क करके जागरुकता का कार्य किया जिसका परिणाम भी दिखा कि समुदाय के लोग बैठक में भागीदरी किये तथा सही लोगों का चुनाव खुली बैठक में हुई।

बेहतर शिक्षा हक अभियान-

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ग्राम्या संस्थान द्वारा सेवापुरी ब्लाक व बड़ागाँव ब्लाक में बेहतर शिक्षा हक अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को प्रेस कान्फ्रेन्स के

बेहतर शिक्षा हक़ अभियान हेतु प्रेस वार्ता

माध्यम से किया गया। 20 अगस्त को शिक्षा विभाग द्वारा रुट मैप मिला उसी के आधार पर 22 अगस्त से 05 सितम्बर तक नई विद्यालय प्रबन्धन समिति के

सत्तनपुर प्राथमिक विद्यालय पर विद्यानय प्रबन्धन समिति का गठन

गठन का कार्य हुआ जिसमें ग्राम्या संस्थान ने नई विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन हेतु 129 स्कूलों में

मदद करने का कार्य किया। जिसके कारण विद्यालय प्रबन्धन समिति में ग्राम्या के संगठन से प्राथमिक विद्यालय में 11 अध्यक्ष जिसमें से 04 महिला व 07 पुरुष, 38 उपाध्यक्ष जिसमें से 37 महिला व 01 पुरुष एवं 129 सदस्य जिसमें से 116 महिला व 13 पुरुष चुने गये हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 04 अध्यक्ष जिसमें से 01 महिला व 03 पुरुष, 09 उपाध्यक्ष जिसमें से सभी महिलाएं एवं 33 सदस्य जिसमें से 26 महिला व 07 पुरुष चुने गये हैं।

महिला मंच के बढ़ते कदम-

जैसा कि आप लोगों ने पिछले अंक में पढ़ा कि महिला मंच की महिलाये कभी स्वास्थ्य तो कभी आंगनबाड़ी, कभी मीड डे मिल पर निगरानी तो कभी राशन में हो रही घटतौली पर नजर रखी और आवाज उठाई। महिला मंच की महिलाओं को पता चला कि स्कूलों में नई विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन होना हैं फिर क्या चल पड़ी बैठकों में शामिल होने के लिए। जिन गाँवों में मंच बना हैं वहा कि लीडर महिलाये अपने साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के साथ गई खुली बैठक करवाई तथा पात्र व बोलने वाली महिला के नाम को प्रस्तावित करवाई जिसका परिणाम रहा कि सेवापुरी ब्लाक व बड़ागांव ब्लाक से महिला मंच की कुल 193 महिलाओं में 5 अध्यक्ष, 46 उपाध्यक्ष व 142 सदस्य के रुप में चयन की गई।

महिला मंच का एक्सपोजर-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवापुरी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवापुरी ब्लाक की महिला मंच की महिलाओं का एक्सपोजर

ब्लाक की महिला मंच की महिलाओं का एक्सपोजर जमुना सेवा सदन व सरोजनी नायडू अस्पताल में कराया गया। दोनों ही अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा स्मार्ट कार्ड से होने वाले फायदे व स्मार्ट कार्ड का प्रयोग कैसे किया जाता है के बारे में विस्तार से बताया और सिस्टम को दिखाया। इस एक्सपोजर में 13 पंचायत के 21 गाँव से कुल 28 महिलायें जानकारी ली।

आइये जाने, समझे क्या होता हैं मनरेगा लेबर बजट-

मनरेगा के गाइड लाइन में मनरेगा लेबर बजट बनाने का प्रावधान हैं इसके लिए 15 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी इसके लिए जिला प्रशासन से पैरवी की गई तो ज्ञात हुआ कि विकास खण्ड स्तर पर गाइड लाइन चली गई हैं लेकिन पंचायत स्तर पर यह गाइड लाइन 3 अगस्त तक नहीं पहुँची। इस संदर्भ में पैक्स द्वारा मनरेगा लेबर बजट बनाने का प्रशिक्षण 26 जुलाई को वाराणसी में आयोजित किया गया जिसमें सेवापुरी व बड़ागाँव के 10 पंचायत के प्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ–साथ ग्राम्या संस्थान की टीम ने भी लेबर बजट

मनरेगा लेबर बजट प्रशिक्षण

बनाने का प्रशिक्षण लिया।

लेबर बजट बनाते समय सबसे पहले मनरेगा में नियोजन प्रक्रिया के चरण के बारे में बताया गया

बरही नेवादा पंचायत में लेबर बजट बनाने हेतु बैठक

इसके बाद अनिवार्य शर्ते क्या होगी तथा इसकी क्या विशेषता होगी। गाँव में खुली बैठक करके जिसमें समुदाय के लोगों की भागीदरी हो उसके बाद सबकी सहमती से गाँव के विकास के लिए कार्यो का प्रस्ताव तैयार किया जाय उसके बाद उसको ब्लाक पर दिया

जाय। यह मनरेगा लेबर बजट 2014–2015 के लिए बनाये जाने की बात की जा रही हैं इसके पिछे क्या हुआ और क्या हो रहा है उसपर न सोचकर आने वाले बजट के बारे में सोचे। इस प्रकार की प्रक्रिया से बनाये गये बजट पर सभी जॉब कार्ड घारकों को 100 दिन का काम मिलेगा। मनरेगा बजट के बारे में जब जानकारी दी जा रही थी तो कोई भी प्रधान इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे उनका कहना था कि अप्रैल माह में हम लोग बजट बनाकर देते हैं और उसी के आधार पर पैसा आता हैं एक साल का बजट कभी भी नहीं बना है तो अब क्या बनेगा। वही समुदाय के लोगों का कहना था कि पहले नहीं बना तो क्या हुआ अब अगर बन रहा हैं तो बजट बनाकर देना चाहिए जिससे हम लोगों को गाँव में काम मिले काम के लिए हमें बाहर ना जाना पड़े। पंचायत सदस्यों का कहना था कि इस बजट को बनाने में हम लोगों की भूमिका होती हैं यह पहली बार सुन रहे हैं हम सभी के बार्डो में काम है लेकिन प्रधान हम लोगों से पूछे तब तो अगर जैसा कि बताया जा रहा उसके आधार पर बजट बनाया जाय तो सभी मजदूरों को काम मिलेगा कोई बाहर नहीं जायेगा। मनरेगा लेबर बजट के तहत ग्राम्या संस्थान द्वारा बड़ागाँव ब्लाक व सेवापुरी ब्लाक के 10 पंचायत के 10 गाँव में अभियान चलाकर जागरुकता का कार्य किया गया।

सामाजिक अंकेक्षण–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। समेकित बाल विकास सेवा बच्चों के मौलिक अधिकारों विशेषकर उनके पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1975 से चलाया जा रहा है, जिनके लिए ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गई है। जीवन जीने का अधिकार को आधार मानकर **31 पंचायत** सेवापुरी विकास खण्ड व **5 पंचायत** बड़ागाँव विकास खण्ड के **कुल 36 पंचायत के 93** आंगनबाड़ी केन्द्रों का (सोशल आडिट) किया गया आडिट से जो तथ्य निकलकर आया वह काफी चौकाने वाला था।

- **93 गाँव में कुल 1031 गर्भवती महिलायें पंजीकृत थी जिसमें से 32 महिलाओं को पोषाहार नहीं मिला।**
- **93 गाँव में कुल 945 धात्री महिलायें पंजीकृत थी जिसमें से 21 महिलाओं को पोषाहार नहीं मिला।**
- **93 गाँव में कुल 5758 किशोरियां पंजीकृत थी जिसमें से 5488 किशोरियों को पोषाहार नहीं मिला।**
- **93 गाँव में कुल 9504 बच्चे पंजीकृत थे जिसमें से 4781 बच्चों को पोषाहार नहीं मिला।**
- **सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक स्कूलों में 45.16 प्रतिशत, 14 प्रतिशत दलित बस्ती में, 19.35 प्रतिशत पंचायत भवन में, 6.45 प्रतिशत किराये के भवन में तथा 15.4 प्रतिशत सरकारी भवन में चलाया जाता है।**
- **मातृ समिति का गठन कागज पर हुआ हैं इसकी बैठकें नहीं होती है पोषाहार के बदले महिलाओं से हस्ताक्षर करा लिया जाता है।**
- **ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन नहीं किया जाता है।**

सोसल आडिट से निकले तथ्यों पर सरकार के साथ 26 सितम्बर को जन संवाद किया जाएगा जिसमें आई0सी0डी0एस0 विभाग के प्रतिनिधि सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, स्वास्थ्य विभाग एंव पंचायत के प्रतिनिधि व समुदाय की महिलाओं को शामिल किया जाएगा।

जानकारी का पिटारा पपेट शो–

बाल विकास परियोजना विभाग में गर्भवती, धात्री, किशोरी व बच्चों के लिए क्या–क्या सुविधा मिलती हैं इसके बारे में पपेट के माध्यम से लोगों को बताने का कार्य किया गया कि–

आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या हैं जैसे–

- 0–6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों की शारीरिक व मानसिक विकास की नींव डालना।
- मृत्यु, बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभागों के बीच प्रभावशाली समन्वय बनाना।
- पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की आवश्यकता एवं देखभाल करने हेतु माताओं की वृद्धि करना।

आंगनबाड़ी की प्रमुख सेवायें–

- पूरक पोषाहार।
- टीकाकरण।
- स्वास्थ्य जाँच।
- स्कूल पूर्व शिक्षा।
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
- निर्देशन एवं संदर्भ सेवायें।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की प्रमुख जिम्मेदारियाँ–

- 3–6 वर्ष के बच्चें को स्कूल पूर्व शिक्षा देना।
- गर्भवती महिलाये व बच्चों का टीकाकरण करवाना।
- कुपोषित बच्चें की पहचान करके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना।
- ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन करना।
- गर्भवती, धात्री एवं 7 माह से 6 वर्ष के बच्चों का पंजीकरण करना व पोषाहार देना।

आज के युवा कल के भविष्य-

भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा युवाओं का है और उनको रोजमर्रा की जिन्दगी में स्वास्थ्य संबन्धित विभिन्न दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे– बाल विवाह, कम उम्र में गर्भ धरण, जेण्डर आधारित भेदभाव, यौन जनित संक्रमण और एच0आई0वी0 व एड्स।

युवाओं के साथ रामडीह सेवापुरी में बैठक

उत्तर प्रदेश जहाँ वर्तमान समय में लगभग 6 करोड़ युवा हैं जिनके लिए स्वास्थ्य और उनसे जुड़ी सूचनाओं का अभाव है। इसी कड़ी में ग्राम्या संस्थान टीम के कदम बढे युवाओं के तरफ। विकास खण्ड सेवापुरी के रामडीह सामुदायिक भवन में जुलाई माह में पहली बार युवाओं के साथ बैठक किया गया जिसमें लगभग 40 युवा शामिल हुए और अपनी समस्या पर चर्चा किये। बैठक से निकल कर आया कि सेवापुरी ब्लाक में युवाओं के लिए कोई मंच नहीं हैं जहाँ पर वह अपनी बात को रख सके इसलिए सबसे पहले युवाओं के लिए कोई मंच बने जहाँ पर वह महीने में एक बार बैठे और अपनी तथा अपने गांव की समस्या को रख सके। युवाओं द्वारा तय किया गया कि वह प्रतिमाह रामडीह में रविवार के दिन बैठेगें और समस्या पर चर्चा करके उस पर कदम उठायेंगे।

आइये जाने 108 है क्या-

भुइली 23–8–13 को सुबह में ममता को प्रसव पीड़ा शुरु हुई। आशा बहू द्वारा 108 नम्बर पर फोन मिलाया तो फोन नहीं लगा इसके बाद आशा ग्राम्या की कार्यकर्ता से मदद के लिए बोली ग्राम्या के कार्यकर्ता द्वारा 108 पर फोन करके सही–सही पता बताया गया इसके बाद 25 मिनट बाद एम्बुलेंस भुइली ममता के घर पर पहुँची और ममता को लेकर अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में पंजीकरण के बाद आशा बोली की ए0एन0एम0 50 या 100 दे दो तब वह हाथ लगायेगी। ममता की सास सावित्री ने कहा कि ए0एन0एम0 हमारे बहू का प्रसव करायेंगी हमें पता है कि सरकारी अस्पताल में पैसा नहीं लगता है इस लिए हम कोई पैसा नहीं देगें और दवा भी बाहर से नहीं लेकर आयेंगे सब यही से मुफ्त में होगा अगर पैसा ही देना होगा तो हम सरकारी अस्पताल में क्यों आयेंगे। ममता को बच्चा पैदा हुआ वह अस्पताल में 24 घंटा रही इसके बाद वापस घर आ गई तीसरे दिन आशा ममता का चेक घर पर जाकर दी।

ओदरहा 10–9–13 को जहीदा को प्रसव पीड़ा होना शुरु हुआ जहीदा के पति ने 108 न0 पर फोन करके प्रसव होने की बात कही फोन करने के आधे घंटे बाद 108 नं0 की एम्बुलेंस जहीदा के घर पर पहुँच गई। जहीदा अपनी जेठानी के साथ सेवापुरी अस्पताल पर गई 2 घंटे के बाद बच्चा पैदा हुआ। प्रसव के बाद पैसो की मांग की गई तो जहीदा की जेठानी ने पैसा देने से इन्कार कर दिया और बोली कि हमे पता हैं कि सरकारी अस्पताल में प्रसव का कोई पैसा नहीं लगता हैं इस लिए हम पैसा नहीं देगे। जहीदा की जेठानी ने मिठाई मंगाकर सबको खिलाया। 2 दिन बाद जहीदा अपने घर वापस आई।

छगो देवी महिला मंच की लीडर अपने पड़ोसी की बहन को प्रसव कराने हेतु बरही नेवादा अस्पताल पर गई ए0एन0एम0 ने देखा और बोली मैं कुछ दवा बाहर से लिख दे रही हूँ जाकर ले आओं छंगो देवी ने कहा कि मैं कोई दवा बाहर से नहीं लाउगी सब दवा यही से मिलेगा अगर नहीं हैं तो बताओ सी0एम0ओ0 को फोन लगाऊँ। ए0एन0एम0 ने प्रसव तो करा दिया लेकिन प्रसव के बाद 500 रु0 मांगने लगी छगो देवी ने कहा कि किस लिए मैं 500 रु0 दू ए0एन0एम0 ने कहा कि प्रसव कराया इस लिए जिस पर छगों देवी ने कहा कि आप को नौकरी मिली है हम लोगों की मदद करने के लिए ना कि पैसा वसूलने के लिए आपको सरकार तनख्वाह देती है कि नहीं फिर हम क्यों पैसा देगे हम पैसा नहीं देगे और 1400 का चेक आप हमारे घर भेजवायेंगी। छगो देवी से हारकर ए0एन0एम0 ने कहा कि ठीक है जाइये एक सप्ताह बाद चेक भी मिला।

ग्राम्या संस्थान

एल0–40, वी0डी0ए0 कालोनी, चाँदमारी,
लालपुर–द्वितीय, पोस्ट–सारनाथ (लमहीं),
वाराणसी–221 007 (उत्तर प्रदेश)
फोन– 0542–2290120, 2290720
Email- bindu.gra@gmail.com,
bindugramya@rediffmail.com

सहयोग- पैक्स